view of the proposals being far more than the availability of naptha/liquid fuels, all the liquid fuel proposals were reviewed by the Government of India and detailed guidelines were issued to the concerned states for recommending projects for liquid fuel linkage within the overall capacity allocated to them (12.000 MW to the country as a whole). The capacity includes allocation of not only naptha, but also other permitted liquid fuels. The States are making project-wise recommendations for provisional fuel linkage.

Monitoring of Private Sector Power Projects

3606. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number and details of private sector investment-based power projects in operation in the each State;

(b) whether Government have taken any steps for Monitoring all the private sector's investment-based power projects;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have also taken any concrete measures for coordinating the power generation sector in the country; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) As on date, Ministry of Power is monitoring 95 proposals for setting up of power projects in the private sector on the Memorandum of Understanding (MoU)/Letter of Intent (LoI). etc. route (costing more than Rs. 100 crores). As per information available the projects on the above mentioned route which have commenced partial generation are given below:

Sl. No.	Name of the Project	Total capacity (MW)	Capacity/ commissioned (MW)
i.	Hazira Combined Cycle Gas Turbine	515	3 × 110
ii.	Jegurupadu Combined Cycle Gas Turbine	216	3 × 45.8
iii.	Godavari Combined Cycle Gas Turbine	208	45.8

(b) and (c) The Ministry of Power is regularly monitoring the progress of all the proposals for setting up of power projects in the private sector, through periodical meetings with the private promoters, concerned State Governments/State Electricity Boards. Central Electricity Authority and the concerned Ministries/Departments of the Government of India.

(d) and (e) The various measures being taken for coordinating the power generation in the country, inter-alia, include addition of capacity, encouraging private sector participation in power generation, better demand side management, energy conservation measures, renovation and modernisation of existing plants, reduction of transmission and distribution losses and effective utilisation of generation by transfer of power from surplus regions, if any, to deficit regions through inter-regional links.

उद्योगों पर विद्युत शुल्क की बकाया राशियां

3607. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उद्योगों पर राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर विद्युत शुल्क बकाया है;

(ख) सरकार द्वारा विद्युत शुल्क की उस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गह हैं;

(ग) क्या कुछ उद्योग विद्युत का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है,

(ङ) राज्य सरकारों को इससे कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(च) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों द्वारा विद्युत के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जिन उद्योगों पर विद्युत टैरिफ संबंधी धनराशि बकाया है उनका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे** देखिए)।

(ख) विद्युत टैरिफ की वसूली करने के लिए निष्कपट मामलों में किस्तों की सुविधा प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक हो बकाया धनराशि की वसूली के लिए आपूर्ति काट दी जाती है और न्यायालय में मामला दर्ज किया जाता है। कुछ राज्यों में टैरिफ और बिलिंग संबंधी विवादग्रस्त मामलों में निर्णय लेने के लिए समझौता समिति का गठन किया गया है।

(ग) से (च) औद्योगिक उपभोक्ताओं का निरीक्षण राज्यों/रा०वि०बो० द्वारा एक नियमित आवधिक कार्य के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी उद्योग विद्युत का अवैध रूप से उपयोग न कर सके। जहां भी बिजली की चोरी और अथवा अवैध उपयोग का पता लगता है वहां कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाती है। इस प्रकार की अनुचित व्यवस्था का पता लगाने के लिए कई राज्यों/रा०बि०बो० में विशेष सतर्कता दलों का गठन किया गया है।

विवरण

उन उद्योगों का ब्यौरा जिनकी तरफ विद्युत टैरिफ की राशि बकाया है

राज्य/रा०बि०बो०	मार्च, 96 के अनुसार बकाया बिजली बिल	100 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि वाले उद्योगों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	58.84	8
2. असम	18.84	3
3. बिहार	541.33	22
4. गुजरात	225.26	50
5. हरियाणा	77.90	6
6. हिमाचल प्रदेश	0.61	शून्य
7. कर्नाटक	264.91	17
8. केरल	65.45	13
9. जम्मू और कश्मीर	23.71	शून्य
10. मध्य प्रदेश	364.00	46
11. महाराष्ट्र	420.37	74
12. मेघालय	0.86	शून्य
13. उड़ीसा	161.19	22
14. पंजाब	9.20	4
15. राजस्थान	83.80	25
16. तमिलनाडु	49.95	3
17. उत्तर प्रदेश	147.05	35

6-116/GIPMR/ND/aa